

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :- मुकेश कुमार मूंड, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. इस्माइल पुत्र गनी खां		1. तहसीलदार, परबतसर
2. गफूर खां पुत्र गनी खां मुसलमान सा. बागोट		2. नायब तहसीलदार भकरी

प्रार्थना पत्र बाबत :- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :- श्री प्रहलादराम मिर्धा , अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजेश कुमार मीणा राजपैरोकार

मुकदमा नम्बर :- 61/2019

निर्णय दिनांक :- 17/02/2020

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाराम मिर्धा ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बागोट के वक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 228 था जिसका कुल रकबा 18-15 बीघा था कालान्तर में इस खसरा नम्बर 288 के बटा नम्बर पड़ गये जो खसरा नम्बर 228 रकबा 6-01 बीघा, 228/2 रकबा 1-12 बीघा, 288/3 रकबा 9-06 बीघा खसरा नम्बर 228/4 रकबा 1-04 बीघा व खसरा नम्बर 228/5 रकबा 0.02 बीघा कुल 18-15 बीघा हैं इस जमीन में 1/2 हिस्सा जाटो का था जो मोतीराम पुत्र बोदूराम , रामदीन पुत्र बोदूराम पेमाराम पुत्र बोदूराम का था शेष 1/2 हिस्से में प्रार्थीगण के बडे पिता इब्राहीम व वादी के पिता गनी दोनो का था। कालन्तर में बोदूराम के लडके मोतीराम , रामदीन व पेमा ने अपना हिस्सा बटा लिया ओर उनका हिस्सा पूर्वी तरफ का 1/2 था और पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा नेनू लुहार मुसलमान के लडको इब्राहीम व गनी का था उक्त जमीन का ज्यादा हिस्सा खसरा नम्बर 228 कंवलद बागोट सड़क के दक्षिण में आयी हुई हैं तथा थोड़ा सा हिस्सा खसरा नम्बर 228/4 सड़क के उत्तर में खसरा नम्बर 554 आया हुआ हैं जो सेटलमेन्ट के नक्श से स्पष्ट साबित होता हैं। इस जमीन बाबत नेनू के लडके इब्राहीम व गनी ने एक वाद इसी न्यायालय में पेश किया था उसमें कोई रास्ता नहीं होने की बात दर्ज की थी और निवेदन किया गया की उनकी अनुपस्थिति में 228 मिन रकबा 5 बिस्वा उनको बिना सुने गलत दर्ज किया हैं तथा यह भी निवेदन किया की खसरा नम्बर 227 व 228 के बीच उत्तर से दक्षिणी कोई रास्ता नहीं हैं उक्त वाद इब्राहीम बनाम सरकार मुकदमां नम्बर 111/93 जिसका निर्णय दिनांक 31.08.2006 को किया गया तथा नेनू के लडके इब्राहीम व गनी का वाद अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त वाद के बाद प्रार्थीगण को कभी इस जमीन में रास्ता होने के बारे में किसी ने जिक्र नही किया तथा इब्राहीम व गनी ने उत्तराधिकारियों ने अपने 1/2 हिस्से का बंटवारा कर लिया 1/4 हिस्सा पूर्वी तरफ का इब्राहीम के उत्तराधिकारियों का तथा 1/4

हिस्सा पश्चिमी तरफ का गनी के लडको का अर्थात् प्रार्थीगण था तथा 1/4 हिस्सा गनी के लडको का था मौके पर आज भी दोनों पक्षकार काविज हैं स्व. इब्राहीम के पुत्र हजारी व फकीर मोहम्मद ने इस जमीन के बंटवारे का दावा किया यह वाद हजारी बनाम गनी मुकदमा संख्या 68/2009 जिसका निर्णय पहले प्राथमिक डिकी के तौर पर हुआ वाद में आरआई व पटवारी हल्का से मौके पर बंटवारा स्कीम मंगवाई जाकर दिनांक 19.12.2011 को निग्रय किया और उस निर्णय के अनुसार हम प्रार्थीगण गनी के पुत्र का स्मर्ण जमीन 1/4 हिस्सा पश्चिमी तरफ रखा गया इब्राहीम के वारिसान का 1/4 हिस्सा पूर्वी तरफ रखा गया ओर इसके पूर्व में 1/2 हिस्सा बोदूराम के वारिसान का रखा गया बंटवारा प्रस्ताव की नकल पेश है। कभी भी खसरा नम्बर 228 में किसी भी स्थान पर रास्ता होने का जिक्र नहीं है इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2011 से नाराज होकर एक अपील हजारी पुत्र इब्राहीम के वारिसान ने आरएए नागौर में पेश की है जिसका निर्णय दिनांक 15.02.2018 को अपीलान्ट हजारी के पक्ष में होकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। आर.ए.ए. नागौर के निर्णय के विरुद्ध अपील राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई है जो विचाराधीन है तथा उसमें प्रार्थीगण को सुनकर दिनांक 22.02.2018 को आदेश दिया है कि विवादित आराजी का उभय पक्ष मौको व राजस्व रिकार्ड की यथारिथति बनायी रखी जावे। इस दौरान पुराने खसरा नम्बर 228 के नये खसरा नम्बर 560, 555, 559, 568 दर्ज किये गये तथा इस इन्द्राज के करने के समय प्रार्थीगण को कभी नहीं सुना गया न ही सुनने का अवसर दिया था। इस जमीन में मौके पर कही पर भी रास्ता नहीं है लेकिन प्रार्थीगण को एक नोटिस नायब तहसीलदार भकरी से दिया गया कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 559 गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण किया है जिसका जबाब देने हेतु जबाब पेश करने हेतु दस्तावेजो पेश करने हेतु समय मांग है, यह नोटिस आने के बाद प्रार्थीगण ने दस्तावेज व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो खसरा नम्बर 228 के नये खसरा नम्बर व नक्शा में इस्माइल व गनी के हिस्से की भूमि के नये खसरा नम्बर 560 जो सड़क के दक्षिण में है ओर 554 जो सड़क के उत्तर में है बना दिये गये हैं तथा इस खसरा नम्बर 560 के पश्चिम में एक रास्ता नक्शा में खसरा नम्बर 559 दर्ज पाया तथा एक रास्ता 559 के पश्चिम में खसरा नम्बर 568 दर्ज पाया इसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण को कभी नहीं सुना गया प्रार्थीगण के पीठ पीछे कार्यवाही की गई है। अभी नायब तहसीलदार भकरी का पद रिक्त होने व उसका चार्ज तहसीलदार परबतसर के पास होने से दिनांक 13.06.2019 को उनके द्वारा निर्णय कर दिया गया है। प्रार्थीगण की जमीन खसरा नम्बर 560 के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 559 एक रास्ता निकालने का आदेश दिया है ओर दूसरा रास्ता ठीक इसी के पश्चिम में खसरा नम्बर 568 दर्ज है इस प्रकार खसरा नम्बर 558, व 560 के बीच दो रास्ते नक्शे में दर्शाये गये हैं लेकिन मौके पर दो रास्ते कतई नहीं हैं अप्रार्थी तहसीलदार परबतसर जबरदस्ती जेसीवी से रास्त निकालने पर



उत्तर है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को काफी निवेदन किया तथा कहा की प्रार्थीगण की जमीन में जो रास्ते दर्शाये गये हैं उक्त रास्ते रेकर्ड व नक्श में कायम करते समय प्रार्थीगण को नहीं सुना गया है एक जगह दो रास्ते आज तक किसी भी जमीन पर रिकार्ड में कहीं पर भी नहीं हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम बागोट के गत खसरा नम्बर 228 जिसके नये खसरा नम्बर 560 हैं में नया रास्ता नहीं निकालने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काशत की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने की इरतदुआ की है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार परबतारार दिनांक 29.07.2019 को जवाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया है कि ग्राम बागोट के पुराना खसरा नम्बर 228 वक्त रोटलमेन्ट कुल रकबा 21 बीघा था नामान्तकरण संख्या 274 द्वारा खसरा नम्बर 228/1 रकबा 2 बीघा गै.मु. सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हो गई शेष रकबा 19 बीघा रहा नामान्तकरण संख्या 370 द्वारा पुराना खसरा नम्बर 228 रकबा 6-18 बीघा में से 228 मिन 5 बिस्वा गौ.मु. रास्ता राज्य सरकार के खाते में चला गया खसरा नम्बर 228 के रकबा नम्बर डल गये खसरा नम्बर 228 रेकर्ड अनुसार गै.मु. रास्ता दर्ज था तथा गौके पर बन्द था क्योंकि खसरा नम्बर 227/3 जो गै.मु. रास्ता रकबा 4 बिस्वा राज. सरकार के पक्ष में समर्पण नामान्तकरण संख्या 783 द्वारा कराया गया था जो खसरा नम्बर 228 के पश्चिम में चिपता हुआ उत्तर से दक्षिण की तरफ रास्ता चालू था इसलिए खसरा नम्बर 228 गै.मु. रास्ता बंद था वर्तमान में खसरा नम्बर 228 पर धारा 91 की कार्यवाही चालू है। खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा रास्ता उपखण्ड अधिकारी परबतारार के आदेश क्रमांक 1109 व 1110 दिनांक 05.08.1983 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 370 से दर्ज हुआ है। राजस्व मण्डल अजमेर से खातेदारी भूमि बाबत स्थगन आदेश हैं राजकीय रास्ते बाबत कोई स्थगन आदेश नहीं हैं खसरा नम्बर 559, 568 व 558 गै.मु. रास्ता दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 558, 559 एक दुसरे के समानान्तर हैं गौके पर एक ही जगह दो रास्ते हैं दोनो के खसरा नम्बर अलग अलग हैं दोनो रास्ते अलग अलग खातेदारो ने राज. सरकार के हक में समर्पण किये हैं दोनो रास्ते एक खातेदार के खेत में से नहीं हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

3. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश होने पर बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सिद्ध करने के लिए तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक हैं जिसका विवरण इस प्रकार है:-



17/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतारार (जा.पैर)

(अ) प्रथम दृष्टया मामला -

इस बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 228 जिसके नये खसरा नम्बर 558 में कोई रास्ता दर्ज नहीं होना प्रतीत होता हो प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी प्रकरण न्यायालय में विवादाधीन रहना बताया है तथा बंटवारा प्रस्ताव आदि लिया जाना बताया है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण स्वयं ने स्वीकार किया है कि इस बाबत भू-मू के उसके इब्राहीम व गनी ने एक दावा उपखण्ड न्यायालय में पेश किया था जिसमें कोई रास्ता नहीं होने की बात दर्ज की थी और निवेदन किया गया की उनकी अनुसन्धिति में खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा रास्ता उनके बिना चुने दर्ज किया गया है वह भी निवेदन किया गया था की खसरा नम्बर 227 व 228 के बीच उत्तर दक्षिण कोई रास्ता नहीं है वह दावा इब्राहीम बनारस सरकार मुकदमा नम्बर 113/1993 दिनांक 31.08.2006 को अस्वीकार किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की जानकारी सन् 1993 से ही है। नामान्तरण संख्या 370 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 228 रकबा 6-16 बीघा भूमि में से खसरा नम्बर 228 मिन रकबा 5 बिस्वा न्यायालय आदेश दिनांक 05.08.1983 से दर्ज हुआ है। खसरा नम्बर 227 में से खातेदारो द्वारा समर्पण करने पर जरिये समर्पण नामान्तरण संख्या 783 द्वारा रास्ता राजकीय खाते में दर्ज हुआ है। जिसकी पुष्टि अप्रार्थीगण द्वारा जबाब के साथ प्रस्तुत नामान्तरणों से होती है। उक्त दोनों रास्तो के वर्तमान खसरा नम्बर 558 व 559 है जो एक दुसरे के समानान्तर हैं जो राजकीय गै.मु. कटाणी रास्ते राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण सिद्ध करने में असफल रहे है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :-

इस बिन्दु को साबित करने का भार भी प्रार्थीगण पर था। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते खसरा नम्बर 558 व 559 गै.मु. रास्ते राजकीय खाते में दर्ज नहीं होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में होना साबित होता हो। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व नामान्तरण की नकलों से स्पष्ट होता है कि दोनों रास्ते विधिवत प्रक्रिया के तहत राजकीय खाते में दर्ज हुए हैं तथा खातेदारो द्वारा समर्पण करने पर रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में हुआ है, रास्ता आम जन की सुविधा के लिय रखा जाता है, उक्त रास्ते को प्रार्थीगण स्वयं द्वारा बन्द कर रखा है राजकीय कटाणी रास्ते के बन्द होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है जिससे असुविधा प्रार्थीगण को नहीं होकर अन्य आमजन को होना प्रतीत होता है जिससे सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में सिद्ध नहीं होता है।

असुविधा का
सन्तुलन
प्रार्थीगण के हक में सिद्ध नहीं होता है।

(स) अपूर्णीय क्षति -

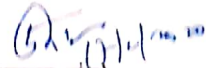
इस बिन्दु को साबित करने का भार भी प्राणीगण पर था। खसरा नम्बर 228 गिन रकबा 5 बिन्दा जिसको वर्तमान खसरा नम्बर 669 है यह खसरा जो पत खसरा नम्बर 228 के मूल खातेदार जो अप्राणीगण के भूजो के साथ 1/2 हिस्से के यह खातेदार बोधुराम जाट नगैरह के वास्तिमान द्वारा दिये जाने पर जसिमे सामान्तकरण संख्या 370 से राजस्व रिजिस्ट्री में दर्ज हुआ है, तथा खसरा नम्बर 669 में मु. शम्भा पत खसरा नम्बर 227 के खातेदारी द्वारा राज हक में समापण करने पर जसिमे सामान्तकरण संख्या 783 के राजस्व रिजिस्ट्री में दर्ज हुआ है। प्राणीगण की खातेदारी भूमि से दोनो की खसती की भूमि कम नहीं हुई है, तथा खसरा आम जलवा व आस पास के खातेदारी की सुविधा के लिये रखा गया है जिस पर अप्राणीगण द्वारा अतिक्रमण कर रखा है जिसको खुलवाया जाता है तो इसमें प्राणीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दोनो खसती राजकीय खाते में दर्ज है। प्राणीगण की भूमि में कोई जबरन खसती कामय नहीं किया जा रहा है। जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्राणीगण अपने हक में सिद्ध करने में असफल रहे है।



संशोक्त विवेचन के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के तीनों बिन्दु प्रथम दुसरे तीसरे भागला, सुविधा का सन्तुजन एवं अपूर्णीय क्षति को प्राणीगण साबित करने में असफल रहे है। जिससे प्राणीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्राणीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 01/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुकेश कुमार मूड)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान सरकार
जयपुर